My suggestion to the Government is that it enacts special laws, which may be used in rare cases when the State is prosecuting dangerous criminals. I would suggest that this law be called the Protection of Material Evidence Act. The legislative intent of this Act would be that in sensitive cases the Government should identify important prosecution witness and if in their opinion a conviction can be recorded on his testimony by the court of law, he should be taken into protective custody before the trial and be given necessary protection so that he may truthfully depose in the court without being subject to coercion, duress and after the material witness delivers the testimony he should be given protection for a prescribed period, to save him from any retribution by the accused or his associates. It is my profound hope that if protection is given to a material witness pre and post criminal trial, the ends of justice can be met. Thank you.

Need to set up an international airport with night landing facilities at Visakhapatnam in Andhra Pradesh

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, Visakhapatnam is one of the most developed industrial cities in Andhra Pradesh. There are a large number of industrial units in Visakhapatnam such as Hindustan Shipyards Ltd., petroleum refinery, Visakhapatnam Port Trust, Dredging Corporation Ltd. and Visakhapatnam Steel Plant. Besides these, other industries are coming up in this area and the city is developing rapidly.

In spite of the importance of Visakhapatnam, unfortunately, there are very poor airport facilities and it also does not have a night landing facilities. There is a need to increase the length of the runway at the existing airport for landing of larger aircraft.

In view of the liberalisation of economic policies of the Government of India and the keen interest shown by the foreign investors in establishing the industrial units and also thrust on exports and imports through Visakhapatnam Port, there is an urgent need for having an international airport at Visakhapatnam.

This issue was raised by me in the Lok Sabha on 28.5.98 and the then Minister for Civil Aviation on 27trv January, 1999, had communicated that a High Level Committee to study the possibility of upgrading Visakhapatnam airport for AB.320 class of aircraft in all weather conditions was taken up by the Government.

In view of the above, the Government must take a final decision on this issue of setting up an international airport and night landing facilities at Visakhapatnam early. Thank you.

Closure of Gurudwara in Kuwait

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया (झारखंड): सभापति जी, मैं अपने विशेष उल्लेख के माध्यम से कुवैत में गुरूद्वारा बंद किए जाने के मामले को विदेश मंत्रालय द्वारा कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का आग्रह करना चाहता हूं।

मान्यवर, 17 अप्रैल,2002 को प्रातःकाल जब समाचार पत्र खोला तो उसके मुखपृष्ठ पर एक ऐसा समाचार था जो न केवल सिख धर्म के अनुयायियों बल्कि वाहे गुरू को मानने एंव श्रद्वा रखने वाले करोड़ों पंथनिरपेक्ष लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। समाचार के अनुसार पश्चिम एशिया के हमारे एक मित्र राष्ट्र कुवैत के सलवा स्थान पर अस्सी के दशक से पहले से बने एंव कार्यरत गुरूद्वारे को वहां की सरकार द्वारा तकनीकी कारणों के अन्तर्गत बन्द कर दिया है। कुवैत में रह रहे एंव कार्यरत 13 हजार सिख एंव अन्य भारतीय जो लाखों की तादात में कुवैत में कार्यरत हैं,इस गुरूद्वारे में आकर सत्संगत का धार्मिक लाभ उठाते थे, जाहिर है अब यह सम्भव नहीं होगा। समाचार के अनुसार कुवैत में केवल तीन धर्म यानी इस्लाम, इसाई एंव जेविस धर्मो के धर्मस्थलों को लाइसेंस दिए जाते हैं परन्तु इस तकनीकी मुद्धे के बावजूद वहां गुरूद्वारा था ओर चल रहा था एंव कुवैत की सरकार ने इसे हटाने या बन्द करने की कभी चेष्टा नहीं की या कभी ऐसा इरादा भी नहीं जताया। अब अचानक ऐसा करने का तात्पर्य समझ में नहीं आता है।

मान्यवर, कुवैत हमारा एक अच्छा एंव हितैषी मित्र राष्ट्र है। भारतीयों का उसके उत्थान में अच्छा-खासा योगदान है और उसने हमेंशा अच्छे एंव बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है हमें विश्वास है कि कुवैत हमारी धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हुए कुवैत के गुरूद्वारे को पूर्व की तरह कार्यरत रहने देगा। अतः मैं सरकार एंव विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर कुवैत सरकार के साथ उठा कर शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाए एंव आहत धार्मिक भावनाओं पर मरहम लगाने का भी कार्य किया जाए। धन्यवाद।

श्री टी. एन.चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ओर यह कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न केवल धार्मिक आस्थाओं का नहीं है बल्कि यह हुमैन राइटस एण्ड यूनिवर्सल हामेन राइटस का प्रश्न भी है जिसका हम यहां अकसर जिक्र करते हैं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (झारखंड): सभापति जी,मैं स्वयं को इससे संबद्व करता हूं।